नई दिल्ली, रविवार
7 अगस्त, 2022
नोएडा
मूल्य ₹ 5.50
पृष्ठ 18+6+4=28

दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

सीयूईटी को लेकर एनटीए की तैयारियां फेल, 53 केंद्रों पर परीक्षा फिर स्थगित 1

उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीते धनखड़ 1

रियल एस्टेट की शुरुआती चुनौतियां आसानी से होंगी दूर

जागरण संवाददाता, नोएडा : आरबीआइ ने फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है। 4.90 फीसद से बढ़कर अब रेपो रेट 5.40 फीसद हो गया है। देश में उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले इस प्रयास का असर अब होम लोन के ब्याज दरों पर पड़ेगा। इसका सीधा असर आम आदमी की ईएमआइ पर पड़ेगा। रेपो रेट की बढ़ोत्तरी पर दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आवश्यक कदम बताया है। इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है बाजार की मांगों में शुरुआती नरमी आएगी, पर संपत्ति खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि व बाजार में नए खरीदारों की भरमार है, इसलिए शुरुआती चुनौतियां बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी।

क्रेडाई वेस्टर्न यूपी अध्यक्ष अमित मोदी ने बताया कि एक बार फिर कर्ज पर ब्याज दरों में वृद्धि कर दी गई है। यह निश्चित रूप से घर खरीदारों की क्षमता को प्रभावित करने वाला है। खासकर मध्यम वर्ग पर इसका असर दिखेगा। इससे अचल संपत्ति बाजार में परियोजनाओं की बिक्री की गति कम हो जाएगी। क्रेडाई एनसीआर अध्यक्ष मनोज गौड़ ने बताया कि इस वृद्धि के साथ रेपो दर अपना चक्र पूरा करते हुए महामारी पूर्व के स्तर पर वापस आ गई है। हमें नहीं लगता कि इसका उपभोक्ताओं की भावनाओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह वर्तमान में उत्साहित है। एसकेए ग्रुप निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि भले ही रियल एस्टेट क्षेत्र रेपो दर को अपरिवर्तित रहना पसंद करता हो, लेकिन जमीनी स्तर की वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

गुलशन ग्रुप निदेशक दीपक कपूर ने बताया कि भले ही सरकार इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव पर लगाम लगाने के प्रयास कर रही है, मगर फिर भी यह अभी कम्फर्ट जोन में नहीं है। आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में, यह समग्र परिदृश्य पर एक तटस्थ प्रभाव डालने वाला है। महागुन ग्रुप निदेशक अमित जैन रेपो दर में वृद्धि ने मुद्रास्फीति की चुनौतियों को कम करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दिखाया है जिसका भारत लंबे समय से सामना कर रहा है।